

$\frac{1}{100} + \frac{1}{68}$



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2010/आषाढ़ 8, 1932

No. 176]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2010/ASADHA 8, 1932

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 जून, 2010

विषय :— ई.यू., सिंगापुर, कोरिया गण. और यू. एस. ए. के मूल के या वहां से निर्यातित प्रोपीलीन ग्लाइकोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

पृष्ठभूमि :

सं 15/26/2008-डीजीएडी— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ई यू. सिंगापुर, कोरिया गण. तथा यू एस ए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) मे मूल के या वहां से निर्यातित प्रोपीलीन ग्लाइकोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004-सी.शु. के तहत मूलतः निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. और यतः इंडियन मेटल एंड फैरो अलायज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार प्राधिकारी ने लागू शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।
3. और यतः दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004 के तहत यथाअधिसूचित पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 13

अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 117/2009 के तहत बढ़ाकर 7 जुलाई, 2010 कर दी गई थी ।

क. प्रक्रिया

4. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी । इस जांच से संबंधित पक्षकारों से निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावलियों का उत्तर देने और लिखित में अपने विचारों को अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।
- ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावलियों का उत्तर देने के लिए अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें । पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार पत्र तथा प्रश्नावलियां संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोग को भेजी गई थीं ।
- iii. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि., चेन्नई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए उत्तर दिया और सूचना/आंकड़ों के साथ अपने अनुरोध दायर किए । कंपनी ने क्षति विश्लेषण करने के लिए सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए ।
- iv. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों ने उत्तर दिया है:

क. मै. शैल ईस्टर्न पेट्रोलिनियम पी पी ई लि.

ख. मै. डाऊ यूरोप जी एम बी एच, स्विटजरलैंड

ग. मै. डाऊ कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) पी टी ई लि.

- v. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है ।
- vi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों तथा साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण को सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा और उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा ।
- vii. प्राधिकारी ने मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि., चेन्नई द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर संभव सीमा तक की ताकि हुई क्षति का विश्लेषण किया जा सके और भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, उसे बनाने और बेचने की लागत निकाली जा सके जिससे यह सुनिश्चित

किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

- viii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 25 फरवरी, 2010 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया । जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस प्रकटन विवरण में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है ।
- ix. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2008- मार्च, 2009 (जांच अवधि) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007, अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।
- x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान मामले में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । इस प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।
- xii. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।
- xiii. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन 21 जून, 2010 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों पर इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।
- xiv. प्राधिकारी ने समस्त हितबद्ध पक्षकारों के संगत अनुरोधों की जांच की है और उन पर इन अंतिम जांच परिणामों में उचित कार्रवाई की है ।
- xv. *** यह चिन्ह इस विवरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच में शामिल उत्पाद समस्त ग्रेडों का प्रापीलीन ग्लाइकोल था । अतः यह निर्णायक समीक्षा होने के कारण इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद अंतर्ग्रस्त है ।

6. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी. शु. उप शीर्ष सं. 2905.3200 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, संबद्ध वस्तु की निकासी अध्याय शीर्ष 2905.39 के अंतर्गत भी की जाती है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र

7. इस समीक्षा जांच की शुरुआत के समय पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार था:-

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।":

8. तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में हाल ही में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।":

9. वर्तमान समीक्षा जांच में मै. मनाली पेट्रोकेमिकल लि. ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. भारत में संबद्ध वस्तु की एकमात्र उत्पादक है और उसका उत्पादन भारतीय उत्पादन का 100% बनता है। अतः मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है।

10. मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. के "आधार" अथवा उसे घरेलू उद्योग समझे जाने के मुद्दे पर किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है अतः भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग है।

11. हितबद्ध पक्षकारों की ओर से प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां

11.1 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

क. लिखित अनुरोधों और उत्तरों को दोहराया जाता है ।

ख. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस तथ्य के मद्देनजर उचित नहीं हैं कि मूल जांच में शुल्क की सिफारिश संदर्भ कीमत के आधार पर की गई थी अतः अनुरोध है कि इस तथ्य पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाए और शुल्क की अवधि आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जाए जो घरेलू उद्योग के हित में होगा ।

ग. प्रकटन विवरण डी जी ए डी ने अंतिम निविष्टियों की लागत के आधार पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर विचार करने का प्रस्ताव किया है । ऐसा कोई प्रस्ताव भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि संबद्ध उत्पाद की क्षति का विश्लेषण अंतिम निविष्टि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए क्योंकि निविष्टि की लागत को लिए जाने से संबद्ध वस्तु से इतर उत्पादों की सूचना के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है ।

11.2 मै. शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) की टिप्पणियां

क. मूल जांच में केवल सीमाशुल्क टैरिफ कोड 29053200 के अंतर्गत वर्गीकरणीय वस्तु, अर्थात् प्रोपीलीन ग्लाइकोल (प्रोपेन-1, 2-डायोल) शामिल थी । यद्यपि, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के क्षेत्र का विस्तार किया है ताकि उसमें सीमाशुल्क टैरिफ कोड 290539 को शामिल किया जा सके । यह एक सुस्थापित कानून है कि निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और विचाराधीन उत्पाद उसी उत्पाद तक सीमित रहेगा जिस पर मूल जांच के दौरान विचार किया गया था । प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान समीक्षा जांच सी. शु. टैरिफ कोड 29053200 के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पादों तक ही सीमित रखा जाए ।

ख. प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि एस ई पी एल की 100% सहायक कंपनी शैल कैमिकल्स सरेया (पी टी ई) लि. (एस सी एस एल) एक पृथक विधि कंपनी है और यह कि एस सी एस एल से प्राप्त कच्ची सामग्री दूरवर्ती आधार पर नहीं थी । इस संबंध में अनुरोध है कि एस सी एस एल एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में प्रचालन नहीं कर रही है । यद्यपि यह एक पृथक विधिक कंपनी है तथापि यह पूर्णतः समेकित लागत केन्द्र के रूप में प्रचालन कर रही है । एस सी एस एल के समग्र उत्पादन की खपत एस ई पी एल द्वारा की जाती है और एस सी एस एल द्वारा किसी अन्य पक्षकार को अपने उत्पादन की बिक्री नहीं की जाती है ।

ग. मूल जांच में डी जी ए डी ने एस सी एस एल को एक समेकित लागत केन्द्र के रूप में विचार करते हुए एस ई पी एल द्वारा सूचित वास्तविक लागत पर विचार किया है। स्थिति वही बनी हुई है जो मूल जांच के दौरान थी।

घ. जांच अवधि के दौरान माह दर माह महसूस की गई ऐसी अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से एकल भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना करना उचित नहीं है। यदि पाटन मार्जिन की गणना माह दर माह आधार पर की जाती है तो इसमें काफी अंतर का पता चलेगा।

ड. यद्यपि, जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि यह नोट किया जाना चाहिए कि आयातों का पहुंच मूल्य भी मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध संदर्भ कीमत से काफी अधिक रहा है।

च. प्राधिकारी द्वारा पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच से यह पता चलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समूची क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा है, लगाई गई पूंजी पर आय एवं लाभ में भी जांच अवधि के दौरान वृद्धि प्रदर्शित हुई है। हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि मौजूदा शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की जाए।

11.3 उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, सिंगापुर (एम टी आई) की टिप्पणियां

एम टी आई ने संक्षिप्त में निम्नानुसार उल्लेख किया है:

- मौजूदा पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में अक्टूबर, 2004 में लागू किया गया था। तथापि, शुल्क लागू होने के बाद बाजारी स्थितियां बदल गई हैं और भारत के लिए सिंगापुर से औसत निर्यात कीमत पिछले पांच वर्षों के दौरान काफी अधिक रही हैं - यद्यपि, भारत द्वारा निर्धारित संदर्भ कीमत से ये 50% से कई बार अधिक रही हैं। वस्तुतः उसके बाद शुल्क लागू नहीं रहा है और उसे समाप्त किए जाने से बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण से हमने यह पाया है कि भारतीय घरेलू उद्योग काफी अच्छी स्थिति में है और उसकी वित्तीय हालत बेहतर है। उसने 121% का क्षमता उपयोग (प्रकटन विवरण का पैरा 37) प्राप्त किया है और वह लगाई गई पूंजी पर 37% आय प्राप्त करने में भी सक्षम है (प्रकटन विवरण का पैरा 52)। अतः यह आपत्तिजनक है कि क्या वस्तुतः अप्रचलित शुल्क समाप्त किए जाने से भारत के बेहतर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति होगी;
- हमने यह पाया है कि विचाराधीन उत्पाद के सिंगापुर के एक निर्यातक मै. शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम पी टी एम लि. (एस ई पी एल) ने इस मामले में डी जी ए डी के साथ पूरा सहयोग किया है।

- एस ई पी एल के अनुरोध से हमने यह नोट किया है कि उनका पाटन मार्जिन खासकर तब नकारात्मक रहा है जब निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना मासिक आधार पर की गई है । अतः सिंगापुर ने यह अनुरोध किया है कि सही पाटन मार्जिन की पुष्टि करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को एस ई पी एल के दावों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए ।

11.4 प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच

क. रिलायंस मामले में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि " ... क्षति रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए हमेशा यह अपेक्षित होता है कि वह निविष्ट की अंतरण कीमत (बाजार मूल्य) पर विचार करे न कि उसकी आबद्ध उत्पादन की वास्तवि लागत पर ... " । तदनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है ।

ख जहां तक एस सी एस एल को एक स्वतंत्र लागत केन्द्र मानते हुए एस ई पी एल द्वारा सूचित प्रोपीलीन ऑक्साइड की वास्तविक लागत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य की गणना हेतु मै. शैल के दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस सी एस एल की अलग विधिक पहचान है और उसने इस बात का प्रदर्शन नहीं किया है कि एस सी एस एल से एस ई पी एल को प्रोपीलीन ऑक्साइड की की गई बिक्री के सौदे दूरवर्ती आधार पर थे । अतः स्वतंत्र क्रेताओं के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री की बिक्री कीमत पर विचार करते हुए तथ उनके आंकड़ों के अनुसार अन्य आंकड़ों को अपनाते हुए बिक्री लागत की पुनः गणना की गई थी ।

पाटन मार्जिन

पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

12. वर्तमान मामले में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है:

- क. मै. शैल ईस्टर्न पैट्रोलिनयम पी पी ई लि.
 ख. मै. डाऊ यूरोप जी एम बी एच, स्विटरजरलैंड
 ग. मै. डाऊ कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) पी टी ई लि.

ड.1. घरेलू उद्योग के अनुरोध

13. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. निर्यातकों ने पूर्णतः त्रुटिपूर्ण उत्तर दायर किए हैं और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है तथा उनके द्वारा दायर उत्तर गोपनीय रूपांतरण की पुनरावृत्ति नहीं है।

ख. उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) द्वारा संबद्ध 100% सहायक कंपनियों शैल कैमिकल्स सरेया (पी टी ई) लि. (एस सी एस एल) और शैल सरेया पायनियर लि. (एस एस पी एल) से प्राप्त प्रोपलीन ऑक्साइड को लागत पर नहीं लिया जा सकता अपितु उसे दूरवर्ती कीमत अर्थात् बाजार कीमत पर लिया जाना चाहिए। एस ई पी एल ने एस सी एस एल को एकीकृत लागत केन्द्र माना है न कि एस एस पी एल ने। एस सी एस एल एक पृथक विधिक कंपनी है और उसे एस ई पी एल द्वारा पूर्णतः एकीकृत लागत केन्द्र के रूप में नहीं माना जा सकता।

ग मै. डाउ यूरोप डी एम बी एच, स्विटजरलैंड तथा मै. डाऊकैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) पी टी ई लि. ने ऐसी संबद्ध कंपनियों के लिए सूचना प्रदान नहीं की है जो सबद्ध वस्तु के कार्यकलाप में संलग्न हैं जबकि विधिक रूप से उन्हें समस्त संबद्ध पक्षकारों की सूचना देनी अपेक्षित थी। अनुरोध है कि डाऊ कैमिकल्स के यूरोप के 17 देशों में संयंत्र हैं और विश्व भर में उसके कई संयंत्र हैं।

ड.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) को छोड़कर किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया है और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के बारे में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

14.1 हालांकि मै. डाऊ यूरोप जी एम बी एच, स्विटजरलैंड तथा मै. डाऊ कैमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) पी टी ई लि. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है परंतु उसे अत्यधिक त्रुटिपूर्ण पाया गया था और इसलिए उनके पास त्रुटि संबंधी पत्र भेजा गया था। परंतु उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही नहीं उन्होंने 25 फरवरी, 2010 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में भी भाग नहीं लिया।

ड.3. सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल)

15. सिंगापुर के संबंध में केवल मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्तर के अवलोकन से

यह पता चलता है कि प्रतिवादी ने घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। यह देखा गया है कि उन्होंने अपनी संबद्ध कंपनी से प्रमुख कच्ची सामग्री की खरीद की है। यद्यपि यह दावा किया गया है कि संबद्ध कंपनी कोई स्वतंत्र लाभ केन्द्र नहीं है, तथापि यह नोट किया जाता है कि संबद्ध कंपनी की अलग विधिक पहचान है। इसके अलावा, यह नहीं बताया गया है कि सौदे दूरवर्ती आधार पर हुए हैं। अतः स्वतंत्र क्रेताओं के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री की बिक्री कीमत को ध्यान में रखते हुए और उनके आंकड़ों के अनुसार अन्य लागत को अपनाते हुए बिक्री लागत की पुनः गणना की गई है। तदपश्चात् 80:20 जांच को लागू करते हुए लाभ योग्य बिक्री के निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री की तुलना बिक्री लागत के साथ की गई है। यह देखा गया है कि केवल ***% घरेलू बिक्रियां लाभ पर की गई थीं। अतः इन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। दावानुसार समायोजन स्वीकार किए गए हैं। अतः सामान्य मूल्य *** अम. डा./मी.ट. बनता है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

16. किए गए उल्लेख के अनुसार मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।
17. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने सिंगापुर को छोड़कर संबद्ध देशों के बारे में सामान्य मूल्य की गणना वर्ल्ड ट्रेड एटलस के आंकड़ों में सूचित प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, घरेलू उद्योग के खपत कारक तथा घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत को अपनाने के बाद की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य ई यू के लिए *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (बल्क के लिए) तथा *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (डिब्बा बंद के लिए); कोरिया गण. के लिए *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (बल्क के लिए) तथा *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (डिब्बा बंद के लिए); तथा यू एस ए के लिए *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (बल्क के लिए) तथा *** अम. डॉ. प्रति मी.ट. (डिब्बा बंद के लिए);

मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) सिंगापुर को छोड़कर सिंगापुर के अन्य किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

ड.4. असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

18. किए गए उल्लेख के अनुसार मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल) को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।
19. मै. शैल इस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल), सिंगापुर द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना/आंकड़ों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा रहा है। मौके पर सत्यापन के दौरान नोट किए गए अनुसार दावा किए गए समायोजनों को

स्वीकार किया गया है। अतः प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण *** अम डा प्रति मी.ट. के रूप में किया है।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम पी टी ई लि. (एस ई पी एल), सिंगापुर को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। ई यू के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और तथ्यों पर विचार किया है।

ड.5 पाटन जारी रहने की संभावना

जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन

अम.डा. प्रति मी.ट. में

	यू एस ए		कोरिया		यूरोपीय संघ		सिंगापुर (एस ई पी एल)	
संबद्ध वस्तु	बल्क	पैकड	बल्क	पैकड	बल्क	पैकड	बल्क	पैकड
सामान्य मूल्य	***	***	***	***	***	***	***	***
निर्यात कीमत	***	***	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	***	***	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	0-5 %	0-5%	(0-5)%	(0-5)%	(5-10)%	(5-10)%	20-25 %	15-20 %

21. पाटन का जारी रहना: प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क व्यावहारिक रूप से अप्रभावी रहा है क्योंकि यह संदर्भ कीमत पर आधारित था जबकि इस अवधि में उत्पादन लागत में भारी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कीमत व्यवहार में किसी खास परिवर्तन का पता नहीं चलता है और यह तब होगा जब लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाएगा।

च. क्षति निर्धारण

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा होने के कारण वास्तविक क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के वास्तविक या संभावित आयातों के संदर्भ में करनी अपेक्षित होती है।

च.1 क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**च.2 घरेलू उद्योग के विचार**

- क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में न केवल वृद्धि हुई है अपितु उसमें समग्र रूप में तथा कुल आयात, मांग एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है ।
- ख. घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमत का हास हुआ है ।
- ग. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2005-06 में 67.23% से घटकर जांच अवधि के दौरान 53.96% हो गया है ।
- घ. घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2007-08 में सर्वोच्च 16875 मी.ट. से घटकर जांच अवधि के दौरान 16069 मी.ट. हो गया। इसी प्रकार क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है ।
- ङ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा वर्ष 2007-08 के सर्वोच्च स्तर से घट गई है ।
- च. बिक्री के % तथा समग्र रूप में व्यक्त पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मालसूची 1% से बढ़कर 4% हो गई है ।
- छ. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उस कीमत से काफी कम रहा है जिसे वह संबद्ध वस्तु की बिक्री पर प्राप्त कर सकता था ।
- ज. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार परिकलित जांच अवधि में लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह जांच अवधि में नकारात्मक रहे हैं ।
- झ. इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग के लिए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वह इस कारोबार में कोई अन्य निवेश करे ।
- ट. निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की अवधि न बढ़ाने का निर्णय लेने से पूर्व यह निष्कर्ष निकालना होता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है । इस प्रकार जांच अवधि के दौरान विभिन्न क्षति कारकों में निवेश का स्तर प्रत्यक्षतः संगत नहीं होता है । यदि संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन जारी रखते हैं तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी और वह जारी रहेगी ।

- ठ. क्षति अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक है । इससे यह पता चलता है कि आरंभ में जिन स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था उन में से किसी शुल्क पर पाटनरोधी शुल्क अभी समाप्त नहीं हुआ है । जैसा कि क्षति कारकों से देखा जा सकेगा कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति जारी है और यह शुल्क वृद्धि का एक स्पष्ट मामला बनता है । इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन का प्रभाव अधिकाधिक गंभीर होगा क्योंकि घरेलू उद्योग निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमत की बराबरी करने के लिए बाध्य होगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को प्रत्यक्ष घाटा और क्षति होगी । जांच अवधि से पूर्व के वर्षों के दौरान संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन भी करते रहे हैं । अतः इस बात में संदेह की कोई गुंजाईश नहीं है कि निर्यातकों के कीमत व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रखेंगे ।
- ड क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में सतत और अत्यधिक वृद्धि होने से संबद्ध देशों के निर्यातकों के संभावित भावी ध्ववहार का मजबूत संकेत मिलता है । यह निश्चित है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण संबद्ध देशों के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से आयातों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी ।
- ढ. इस बात की प्रबल संभावना है कि संबद्ध देशों से भारी पाटन जारी रहा हो और इसमें घरेलू उद्योग की स्थिति आगे और खराब हुई हो और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उसके लाभ में वृद्धि हुई हो ।

च.3 निर्यातकों के विचार

- क बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की अपनी असमर्थता के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मुख्यतः गिरावट आई है । इसके अलावा उसके पास उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है ।
- ख. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग समीक्षा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 100% से अधिक रहा है । वार्षिक रिपोर्ट में सूचित और घरेलू उद्योग के उत्तर में उल्लिखित क्षमता के आंकड़ों के बीच अंतर है ।
- ग. घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार उसे लाभ प्राप्त हुआ है । कम कीमत पर कोई बिंदी नहीं हुई है ।
- घ पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उसने लाभ कमाया है और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभान्ज भी घोषित किया है ।
- ड अपर्याप्त घरेलू आपूर्ति के कारण प्रोग्रिलीन ग्लाइकोर्ड के घरेलू प्रयोक्ताओं के पास संबद्ध वस्तु के आयात के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है ।

ड.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने क्षति जांच के बारे में दिए गए तर्कों को नोट किया है और उन्होंने उठाए गए मुद्दों पर उचित स्थानों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है।

24. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

25. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

च.5 क्षति जारी रहने की संभावना

26. प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान निष्पादन के आधार पर इस बात की सर्वप्रथम जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।

27. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव और कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके

प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

च.6 मात्रात्मक प्रभाव

मांग का निर्धारण

28. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	5384	9077	12956	11184
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	2089	3199	1648	2018
कुल आयातक	मी.ट.	7473	12276	14604	13201
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	15331	16359	17502	15473
मांग	मी.ट.	22804	28635	32106	28674

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 25.75 % की वृद्धि हुई है ।

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

30. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह उपबंध है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ... ।" इस प्रकार पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों ने समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

31. निम्नलिखित तालिका में आयात की मात्रा और बाजार हिस्से की संक्षिप्त स्थिति दी गई है:-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निम्नलिखित से आयात					
संबद्ध देश	मी.ट.	5384	9077	12956	11184
अन्य देश	मी.ट.	2089	3199	1648	2018
कुल आयात	मी.ट.	7,473	12,276	14,604	13,201
भारतीय उत्पादन	मी.ट.	15,950	16,426	16,875	16,069
मांग	मी.ट.	22,804	28,635	32,106	28,674
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	72.05%	73.94%	88.72%	84.72%

उत्पादन	%	33.75%	55.26%	76.78%	69.60%
खपत	%	23.61%	31.70%	40.35%	39.00%
गांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	67.23%	57.13%	54.51%	53.96%

उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (i) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- (ii) जांच अवधि में संबद्ध देशों से हुए आयात में कुल आयातों, भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है।
- (iii) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

32. घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कीमत प्रभाव का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। कीमत कटौती की मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति की गणना समस्त रिबेटों और करों को घटाने के बाद की गई है।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती की राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती की रेंज	% रेंज	(0-5)%	0-5%	5-10%	(0-5)%

33. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही थी, तथापि जांच अवधि में कीमत में नकारात्मक कटौती देखी गई है।

कीमत हास/न्यूनीकरण

34. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का हास/न्यूनीकरण हुआ है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत के साथ-साथ उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	103	115
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	93	108
संबद्ध देशों से आयातों की औसत पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	88	114

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि की तुलना में उत्पादन लागत तथा निवल बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई है तथापि, निवल बिक्री प्राप्ति में भी वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी अधिक रही है ।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

36. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

37. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
स्थापित क्षमता	मी.ट.	13250	13250	13250	13250
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	15950	16426	16875	16069
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	101
क्षमता उपयोग (%)	%	120%	124%	127%	121%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	101
बिक्री मात्रा	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	112	100
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	114	101

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि:

- (क) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री में वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हुई है परंतु जांच अवधि वर्ष 2008-09 में गिरावट आई है ।
- (ख) घरेलू उद्योग वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक अपने क्षमता स्तर से अधिक उत्पादन करने में समर्थ रहा है । दूसरे शब्दों में समूची क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा है ।

लाभप्रदत्ता

38. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और लाभ/हानि निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	103	116
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	93	108
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	45	71
घरेलू बिक्री पर लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	88	51	71
ब्याज	लाख रुपए	***	***	***	***
कर पूर्व लाभ/हानि	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	51	73
निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	59	138
कार्यशील पूंजी	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	100	45
लगाई गई पूंजी - एन एफ ए	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	81	87
लगाई गई पूंजी पर आय (एन एफ ए आधार पर)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	63	84
मूल्यहास	रु./लाख	***	***	***	***

नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	52	72

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक गिरावट आई है परंतु जांच अवधि में सुधार हुआ है । लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में भी लाभ के समान प्रवृत्ति रही है ।
40. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि वर्ष दर वर्ष आधार पर घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप घरेलू बिक्री कीमत को बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा । बिक्री लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से अधिक रही है । तथापि, इसके बावजूद घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर ***% आय प्राप्त करने में समर्थ रहा है ।

बाजार हिस्सा

41. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से और भारत में संबद्ध वस्तु की कुल मांग में संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना से यह पता चलता है कि यद्यपि उत्पाद की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है तथापि क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है जगकि संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है । परंतु इसे 100% से अधिक क्षमता उपयोग के संदर्भ में देखने की जरूरत है ।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
संबद्ध देश	%	23.61%	31.70%	40.35%	39%
अन्य देश	%	9.16%	11.17%	5.13%	7.04%
घरेलू उद्योग	%	67.23%	57.13%	54.51%	53.96%

रोजगार तथा मजदूरी

42. रोजगार तथा मजदूरी से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
रोजगार सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	100	100	100
मजदूरी लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	126	128	140

उत्पादकता

43. उत्पादन प्रति कर्मचारी और उत्पादन प्रति दिवस के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्पादन	मी.ट.	15950	16426	16875	16069
रोजगार	सं.	***	***	***	***
उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	106	101

44. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक सुधार हुआ परंतु उसके बाद गिरावट आई। समूची क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या स्थिर रही है और इसका स्पष्ट तौर पर इसी अवधि में प्रदत्त वेतन और कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा रोजगार और प्रदत्त मजदूरी वर्तमान मामले में क्षति के मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं हो सकता है।

मालसूची

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
माल सूची मी.ट. में	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	63	48
बिक्री मी.ट. में	मी.ट.	***	***	***	***
बिक्री दिवसों की संख्या के लिए मालसूची	दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	56	48

45. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि की तुलना में बिक्री दिवसों की संख्या के संबंध में औसत मालसूची में गिरावट आई है। आधार वर्ष में यह *** दिवसों के समतुल्य थी जबकि जांच अवधि में यह घटकर *** दिवस रह गई।

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

46. जांच अवधि के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पर्याप्त लाभ के मद्देनजर पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि यू एस ए और सिंगापुर के संदर्भ में पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है परंतु वह कोरिया गण. और यूरोपीय संघ के संबंध में नकारात्मक है।

48. वृद्धि

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग जैसे मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि वर्ष 2007-08 तक सकारात्मक रही है। तथापि, जांच अवधि के दौरान इन मापदंडों में गिरावट देखी गई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक गिरावट आई है परंतु जांच अवधि में सुधार हुआ है। लगाई गई पूँजी पर आय और नकद लाभ में प्रवृत्ति लाभ के समान रही है।

क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

49. घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी की जानकारी में घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच हेतु निम्नलिखित तथ्य लाए गए हैं। घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है कि:

- (i) संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में सामग्री का पाटन किया जा रहा है। यद्यपि, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है तथापि, निर्यातकों की निर्यात कीमत में आनुपातिक वृद्धि का पता नहीं चला है जिससे निर्यातकों द्वारा लागत खपाने का पता चलता है।
- (ii) यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
- (iii) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत उस कीमत से काफी कम रही है जिसे घरेलू उद्योग को प्राप्त करना चाहिए था।
- (iv) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- (v) उत्पादकों के पास पर्याप्त बेशी क्षमता है और उनकी घरेलू मांग उनके द्वारा सृजित क्षमता से काफी कम है।

प्राधिकारी

50. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध देशों से आयात जारी रहे हैं और उनमें वृद्धि हुई है, तथापि मात्रात्मक रूप में उसका प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है क्योंकि घरेलू उद्योग वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक (अर्थात् समूची क्षति अवधि के दौरान) अपने क्षमता स्तर से अधिक उत्पादन करने में समर्थ रहा है। आयातों का बिक्री पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।
52. जहां तक घरेलू उद्योग की कीमत पर आयातों के प्रभावों का संबंध है, यह भी प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग लगाई गई पूंजी पर ***% आय (एन एफ ए आधार पर) वसूलने में समर्थ रहा है।
53. यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं के कारण संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किए जाने की संभावना है परंतु इस दावे की उन्होंने पुष्टि नहीं की है।
54. घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और पाटन की भरपाई करने के लिए शुल्क का निरंतर जारी रखा जाना अनिवार्य है।

च.4 कारणात्मक संबंध

55. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि निर्णायक समीक्षाओं में कारणात्मक संबंध का विश्लेषण अपेक्षित नहीं होता है। इस संबंध में उन्होंने मैक्सिको से ऑयल कंट्री टेबुलर गुड्स (डब्ल्यू टी/डी एस 282/ए बी/आर दिनांक 2 नवंबर, 2005) के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के निम्नलिखित उद्धरणों पर भरोसा किया है :

"118. अतः हम मैक्सिको के साथ इस बात पर सहमत हैं कि इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख गैट 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के विभिन्न उपबंधों में किया गया है। संयुक्त राज्य ने भी इस सिद्धांत पर प्रश्न नहीं उठाया है। तथापि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत की गई किसी "समीक्षा" में पाटन एवं क्षति के बीच कारण संबंध की पुष्टि नए सिरे से किए जाने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 11.3 में उल्लिखित "समीक्षा" मूल जांच से "भिन्न" प्रायोजन वाली एक "अलग" प्रक्रिया होती है।"

"119. अपीलीय निकाय ने यह रेखांकित किया है कि "किसी निर्णायक समीक्षा में किए जाने वाले निर्धारण का स्वरूप मूल जांच में किए जाने वाले निर्धारण से कुछ अनिवार्य पहलुओं में भिन्न होता है", और "अतः मूल जांच में लागू सिद्धांत समीक्षा प्रक्रिया में स्वतः लागू हो जाते हैं ।"

"एक्स. जांच परिणाम एवं निष्कर्ष"

219. इस रिपोर्ट में उल्लिखित कारणों से अपीलीय निकाय:

(क) कारणात्मक संबंध के बारे में:

(ख) यह पाया गया है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत किसी निर्णायक समीक्षा निर्धारण में विधिक अनिवार्यता के रूप में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए यूएसआईटीसी के लिए इस विवादाग्रस्त मुद्दे में निर्णायक समीक्षा में क्षति की संभावना का निर्धारण करने में किसी संबंध को प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है"

56. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि किसी निर्णायक समीक्षा के मामले में कारणात्मक संबंध की अपेक्षा को लागू न करने का बेहतर तकनीकी एवं तर्कसम्मत कारण है। पाटनरोधी शुल्क की अवधि में विस्तार करने की परिकल्पना तब भी की गई है जब समीक्षा जांच अवधि में कोई आयात न भी हुआ हो। इसके अलावा, धारा 9 क (5) के अंतर्गत शुल्क की अवधि को बढ़ाने की जांच इसलिए की जाती है कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

57. प्राधिकारी ने किसी निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध के महत्व के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है। धारा 9 क(5) के अंतर्गत यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति की संभावना और शुल्क जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित है भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात किया गया हो अथवा नहीं। निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुसंगत परंपरा भी रही है और यह इस मुद्दे पर न्यायशास्त्र से परे भी नहीं है।

58. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तर्कों के गुणदोष पर गौर किए बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध की जांच की है जिस पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अन्य देशों से मात्रा एवं कीमत

59. आयात संबंधी आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि एक अन्य देश अर्थात् चीन जन गण से संबद्ध वस्तु का पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर आयात हुआ है। घरेलू उद्योग ने इस आशय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्यों इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना में इन आयातों की अनदेखी की जा रही है।

मांग में कमी और अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

60. यह नोट किया जाता है कि मांग में कोई कमी नहीं हुई है। दूसरी ओर आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में लगभग ***% की वृद्धि हुई है। खपत की पद्धति में परिवर्तन का भी कोई संकेत नहीं है जैसा कि घरेलू उद्योग की बिक्री पद्धति से स्पष्ट होता है।

विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

61. संबद्ध वस्तु का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होता है और वह देश में मुक्त रूप से आयात के योग्य है। घरेलू उद्योग एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के अनुसार निर्धारित होती है। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन

62. किसी भी पक्षकार ने प्रौद्योगिकी के बारे में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का अति अल्प मात्रा में निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले में केवल घरेलू प्रचालनों के बारे में ही लाभप्रदता और कीमत के अन्य मापदंडों पर विचार किया है।

लाभप्रदता

63. लाभप्रदता में कोई गिरावट नहीं आई है और इसमें क्षति जांच अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

64. क्षति मार्जिन की मात्रा

क. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण समग्र रूप में किया गया है।

ख. क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ की गई है जो निम्नानुसार है :

65. क्षति मार्जिन की गणना

क्षति मार्जिन से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	इकाई	2008-09
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत		
ई यू	रु./मी.ट.	***
कोरिया	रु./मी.ट.	***
सिंगापुर	रु./मी.ट.	***
यू एस ए	रु./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन		
ई यू	रु./मी.ट.	(***)
कोरिया	रु./मी.ट.	***
सिंगापुर	रु./मी.ट.	***
यू एस ए	रु./मी.ट.	(***)
क्षति मार्जिन %		
ई यू	%	(***)
कोरिया	%	***
सिंगापुर	%	***
यू एस ए	%	(***)
क्षति मार्जिन रेंज		
ई यू	% Range	(7-12)
कोरिया	% Range	2-6
सिंगापुर	% Range	12-18
यू एस ए	% Range	(1-5)

यह नोट किया जाता है कि कोरिया गण. और सिंगापुर से क्षति मार्जिन सकारात्मक है और ई यू तथा यू एस ए से क्षति मार्जिन नकारात्मक है ।

अंतिम जांच परिणाम

66. पूर्वोक्त पर और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है और यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है ।
67. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004 के तहत यथाअधिसूचित और बाद में अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 13 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 117/2009 के तहत 7 जुलाई, 2010 तक समय विस्तारित संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं ।
68. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 29th June, 2010

Subject :—Sunset Review of Anti-dumping duty on imports of Propylene Glycol originating in or exported from EU, Singapore, Korea RP and USA.

BACKGROUND :

No. 15/26/2008-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No.105/2004-Customs, dated the 8th October 2004 on import of Propylene Glycol (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from EU, Singapore, Korea RP and USA (hereinafter also referred to as subject countries).

2. And whereas, in view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd v/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 31st March 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the Sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. And whereas, the antidumping duty as notified vide Notification No. 105/2004 dated 8th October 2004 was extended up to 7th July 2010 vide notification No.117/2009 dated 13th October 2009 in terms of Section 9 (A) (5) of the Act.

A. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed:
 - i. The Authority sent copies of the initiation notification, to all known exporters/ producers of the subject goods in the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.

- ii. The Embassies/High Commission of the subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaires within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaires was sent to Embassies/High Commission of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iii. In response to the initiation notification, M/s. Manali Petrochemicals Ltd., Chennai responded and filed their submissions along with information/data, *inter alia*, seeking extension of the anti-dumping duties. The company submitted the information/data for undertaking the injury analysis.
- iv. In response to the initiation notification, the following exporters from subject countries have responded:
 - a. M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd.
 - b. M/s Dow Europe GmbH, Switzerland
 - c. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte. Ltd.
- v. In response to the initiation notification, no other interested party has responded.
- vi. The Authority made available non-confidential version of the information/data and evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- vii. The Authority examined the information furnished by M/s. Manali Petrochemicals Ltd., Chennai to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the injury suffered and to work out the cost of production, cost to make and sell the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- viii. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 25th February 2010. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this disclosure statement.
- ix. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2008 – March 2009 (POI). However, injury analysis covers the periods April 2005–March 2006, April 2006–March 2007, April 2007–March 2008 and the POI.
- x. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant matter were disclosed to the known interested parties. The comments received on this disclosure statement have been duly considered in the final findings.
- xi. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xiii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to know interested parties on 21st June 2010. Responses filed by the interested parties have been duly considered in these findings.
- xiv. The relevant submissions of all the interested parties have been examined by the Authority and have been appropriately dealt with in these final findings.
- xv. *** In this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 5. The product involved in the original investigation was Propylene Glycol of all grades. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation.
- 6. The subject goods are classified under Customs sub-heading no. 2905.3200 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the subject goods are also cleared under Chapter Headings 2905.39. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

C. STANDING & SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 7. At the time of the initiation of this review investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only":

- 8. However, the Rule 2(b) of the AD Rules has recently been amended to read as:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

9. In the present review investigation, M/s Manali Petrochemicals Ltd. has responded to the initiation notification. The Authority notes that M/s Manali Petrochemicals Ltd. is the sole producer of the subject goods in India and thus accounts for 100% of the Indian production. Therefore, M/s Manali Petrochemicals Ltd. constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules.
10. No comments have been received from any interested party on the issues of 'Standing' or the status of the M/s Manali Petrochemicals Ltd. being considered as the domestic industry. Therefore, M/s Manali Petrochemicals Ltd. who represents the total production of the subject goods in India constitutes the domestic industry for the purpose of the current investigation.

11. Comments on disclosure statement from interested parties

11.1 Comments of Domestic Industry

- a. The written submissions and the rejoinder submissions are reiterated.
- b. The conclusions drawn by the Authority in the disclosure statement are not appropriate in view of the fact that the duty in the original investigation was recommended based on the reference price. It is, therefore, requested that this fact may be considered in the final findings and the duties may be extended for another term of five years which would be in the interest of the domestic industry.
- c. In the disclosure statement DGAD proposes to consider the profitability of the domestic industry based on the cost of the penultimate inputs. Such an approach is against the directions of the Hon'ble supreme court of India wherein it has been clearly stated that the injury of the concerned product is to be analyzed by taking into account the market value of the penultimate inputs as taking the cost of the inputs into account would lead to an analysis based on information of products other than the subject goods.

11.2 Comments of M/s Shell Eastern Petroleum Pte Ltd. (SEPL)

- a. The original investigation covered only goods classifiable under Customs Tariffs Code 29053200, *i.e.*, Propylene Glycol (Propane-1, 2-diol). Whereas in the present sunset review, the Authority has broadened the scope to include goods classifiable under Customs Tariffs Code 290539. It is a well established law that the scope of the product under investigation cannot be amended during the sunset review investigation and the product under investigation shall be restricted to the same product as was considered during the original investigation. It is submitted to the Authority that the present review investigation shall be restricted to products classified under Custom Tariffs Code 29053200 only.
- b. The Authority has stated that Shell Chemicals Seraya (Pte.) Ltd (SCSL), a 100% subsidiary of SEPL, as a separate legal entity and that the raw material procured from SCSL was not at arm's length. In this regard, it is submitted that SCSL is not operating as an independent entity. Though it is a separate legal entity, it is operating as a fully integrated cost centre. The entire production of SCSL is absorbed by SEPL and SCSL does not sell its production to any other party.

- c. In the original investigation, DGAD has taken the actual costs reported by SEPL considering SCSL as an integrated cost centre. The position continues to remain the same as it was during the original investigation.
- d. In view of such volatility experienced during the POI from month to month, it is not appropriate to calculate a single weighted average dumping margin for the POI as a whole. If the dumping margin is calculated on a month to month basis, it will show a significantly different trend.
- e. Even though the imports have increased during the investigation period, it should be noted that the landed value of imports have also remained significantly higher than the reference price fixed by the Authority in the original investigation.
- f. Examination of likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury by the Authority reveals that the withdrawal of duties will not lead to recurrence of injury to the domestic industry. The capacity utilization has been more than 100% throughout the injury period, profits and return on capital employed have also shown increasing trend during the investigation period. We request the Authority to recommend termination of the existing duties.

11.3 Comments of Ministry of Trade & Industry, Singapore.(MTI)

MTI, in brief, has stated the following:

- The existing AD duties were imposed in October, 2004 in the form of a reference price. However, market conditions changed as the duties came into force, and the average export prices from Singapore to India have remained significantly high throughout the past five years – being even at certain times higher by over 50% of the reference price fixed by India. *DE facto* then, the duties have been inoperative and their withdrawal would not cause an adverse impact to the market;
- From the Disclosure Statement issued by the Designated Authority, we observe that the Indian domestic industry is in very good operational and financial health. It has achieved a capacity utilization level of 121% (paragraph 37 of the Disclosure Statement) and has even been able to realise a 37% return on capital employed (paragraph 52 of the Disclosure Statement). It is therefore questionable if the withdrawal of the *de facto* inoperative duties would lead to recurrence of material injury to India's healthy domestic industry;
- We have observed that one of Singapore exporters of the product under consideration, M/s. Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. ("SEPL"), has fully cooperated with the DGAD in this case; and
- We note from SEPL's submissions that their dumping margin has been negative, particularly, when the export prices and normal values have been compared on a monthly basis. Singapore, therefore, requests that the Designated Authority carefully examine SEPL's claims in order to establish accurate dumping margins.

11.4 Examination by the Authority on Comments received on Disclosure Statement

- a. In the Reliance Judgement, Hon'ble Supreme Court has opined that "... for the purpose of determination of NIP, the DA is always required to take into consideration the transfer price (market value) of the inputs and not their actual cost of captive production...." The NIP has been determined accordingly.
- b. As regard the claim of M/s Shell for computation of Normal value considering the actual cost of Propylene Oxide as reported by SEPL considering SCSL as an independent cost centre, the Authority notes that SCSL has a distinct legal personality and it has not been demonstrated that the transactions of sale of Propylene Oxide from SCSL to SEPL were at arms' length. Therefore, the Cost of sales was re-computed considering the sale prices of major raw material to independent buyers and by adopting other costs as per their data.

DUMPING MARGIN

Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

12. In the present case, except the following exporters/ producers, no other exporter/ producer from the subject countries has responded:

- a. M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd.
- b. M/s Dow Europe GmbH, Switzerland
- c. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte. Ltd.

E.1. Submissions made by the Domestic Industry

13. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The exporters have provided completely deficient responses and claimed excessive confidentiality and the response filed them is not a replica of the confidential version.
- b. Propylene oxide sourced by M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) from related 100% subsidiaries Shell Chemicals Seraya (Pte.) Ltd (SCSL) and Shell Seraya Pioneer Ltd. (SSPL) for the purpose of determination of cost of production cannot be taken at the cost but ought to be taken at arm's length price i.e. market price. SEPL has treated SCSL as integrated cost centre but not SSPL. SCSL is a separate legal entity and cannot be treated as fully integrated cost centre by SEPL.
- c. M/s Dow Europe GmbH, Switzerland and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte. Ltd. have not provided the information for all the related companies who are engaged in the activity of the subject goods whereas legally they are required to give the information for all the related parties. It is submitted that Dow Chemical has its plants in as many as 17 countries in Europe and several other plants world over.

E.2. Examination by the Authority

14. Except M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL), neither any other exporter/producer has filed the questionnaires' response in the form and manner prescribed, nor has any interested party offered any comment or submissions with regard to the Normal value, Export price and determination of the dumping margin.
- 14.1 While M/s Dow Europe GmbH, Switzerland and M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte. Ltd. responded to the exporter's questionnaire but the same was found to be grossly deficient and hence a detailed deficiency letter was sent to them. However, no response was filed by them in response thereto. Not only this, they did not even participate in the Public hearing held on 25th February 2010.

E.3. Determination of Normal Value for Co-operative exporters/producers**M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL)**

15. In respect of Singapore, only M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore has filed their questionnaire's response in the form and manner prescribed. A perusal of the response shows that the respondent has claimed the determination of the Normal value on the basis of their domestic sales. It is seen that they have procured the major raw material from its affiliate. Though, it was claimed that the affiliate was not an independent profit centre, but it is noted that the affiliate has a distinct legal personality. Besides, it has not been demonstrated the transactions were at arms' length. Therefore, the Cost of sales was re-computed considering the sale prices of major raw material to independent buyers and by adopting other costs as per their data. Thereafter, the domestic sales have been compared with the cost of sales to determine the profitable sales for applying the 80:20 test. It is seen that only ***% of the domestic sales were made at a profit. Hence, the same have been considered for determination of the Normal value. The adjustments as claimed have been accepted. Thus, the Normal value works out as *** US \$/MT.

Normal value for Non-cooperative exporters/producers

16. As stated, except M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore, none of the exporters/producers from the subject countries has cooperated with the Authority in this investigation.
17. In view of the above, the Authority has-constructed the Normal values, in respect of the subject countries except Singapore, by adopting the international prices of the major raw material as reported in World Trade Atlas data, consumption factor of domestic industry and conversion cost of domestic industry. The Normal values so determined work out as US\$ *** per MT (for bulk) and US\$ *** per MT (for packed) for EU; US\$ *** per MT (for bulk) and US\$ *** per MT (for packed) for Korea RP; and US\$ *** per MT (for bulk) and US\$ *** per MT (for packed) for USA.

As no other exporter/producer from Singapore except M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value based on the facts available on record.

E.4. Export Price for Co-operative exporters/producers

18. As stated, except M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore, none of the exporters/producers from the subject countries has cooperated with the Authority in this investigation.
19. The information/data submitted by M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore and verified by the Authority is being relied upon for the determination of the export price. The adjustments claimed have been accepted, as noted during the spot verification. Thus, the Authority has determined the export price for the exporter as US \$ *** per MT.
20. The Authority notes that except M/s Shell Eastern Petroleum Pte. Ltd. (SEPL) Singapore, none of the exporters / producers from the subject countries has cooperated with the Authority in this investigation. In view of non-cooperation by the exporters / producers in EU, the Authority has considered information and facts available on record.

E.5 Likelihood of continuation of dumping**Dumping Margin during the POI****In US \$ per MT**

	USA		KOREA		European Union		Singapore (SEPL)	
Subject goods	Bulk	Packed	Bulk	Packed	Bulk	Packed	Bulk	Packed
Normal Value	***	***	***	***	***	***	***	***
Export Price	***	***	***	***	***	***	***	***
Dumping Margin	***	***	***	***	***	***	***	***
Dumping Margin %	0-5 %	0-5%	(0-5)%	(0-5)%	(5-10)%	(5-10)%	20-25 %	15-20 %

21. **Recurrence of Dumping:** The Authority notes that anti-dumping duty in force has been practically ineffective as it was based on reference price, whereas the cost of production has significantly changed over time. Thus, there does not appear to be any significant change in the price behaviour of the subject goods from the subject countries, if the anti-dumping duty ceases to operate.

F. INJURY ASSESSMENT

22. The Authority notes that this being a Sunset review of the anti-dumping duty already in force, likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject countries.

F.1 Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury**F.2 Views of Domestic Industry**

- a. The volume of dumped imports from the subject countries have increased and have not only registered an increase in absolute terms but also increased in relation to total imports, demand and domestic production.
- b. The increase in the domestic selling prices is substantially lower than the increase in the cost of production which is a clear indication that the domestic prices have been suppressed by the dumped imports from the subject countries.
- c. The market share of domestic industry has declined from 67.23% in 2005-2006 to 53.96% during the period of investigation due to the presence of dumped imports.
- d. The production of the domestic industry has declined from a peak of 16875 MT in 2007-2008 to 16069 MT during the period of investigation. Similarly, the capacity utilization of the domestic industry has also declined over the injury investigation period.
- e. The sales volume of the domestic industry has declined in the period of investigation from a peak level in the year 2007-08.
- f. The inventories in the POI as compared to the preceding year have gone up from 1% to 4% when expressed as a percentage of sales as well as in absolute terms.
- g. The landed value of the product under consideration from the subject countries is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods.
- h. The profitability, return on investment and cash flow in the present investigation calculated in accordance with the decision of the Hon'ble Supreme Court in the Reliance Industries are negative in the POI.
- i. Under the circumstances, it would not be feasible for the Domestic Industry to make any further investments in this business.
- j. In SSR investigation, the Authority has to reach a conclusion that there is no possibility of any injury to the domestic industry from the dumped imports from the subject countries before deciding not to extend the anti-dumping duties. Thus, the level of improvement in the various injury factors per se during the period of investigation is not directly relevant. If the exporters from the subject countries continue to dump, it is a clear indicator that injury to the domestic industry would recur or continue once the duties are removed.
- k. The dumping margin from each of the subject countries is significant during the period of investigation. It indicates that the dumping has not ceased to exist from any of the sources on which anti-dumping duties were imposed initially. As would be seen from the injury factors, injury to the domestic industry continues despite the imposition of anti-dumping duties and there is a clear case for enhancement of duties. Further, it is also clear that if anti-dumping duties are removed, the impact of dumping would be much more serious as the domestic industry would be forced to match the prices offered by the exporters resulting in direct losses and injury to the domestic industry. The exporters from the subject countries have also indulged in the dumping during the years prior to POI. This shows beyond an iota of doubt that there is no change in the pricing behaviour of the exporters and they will continue to export at dumped prices.
- l. The consistent increase and significant imports from the subject countries during the injury investigation period give a clear and strong indication about the likely future behaviour of the exporters from subject countries. It is certain that the dumped imports

from the subject countries in all probability would surge in case anti-dumping duties are lifted against the subject countries and the domestic industry would continue to be injured.

- m. There is every possibility that the severe dumping from the subject countries would continue and recur and further deteriorate the position of the domestic industry and increase its losses if the duties are not extended.

F.3 Views of Exporters

- a. The market share of the domestic industry fell mainly due to its inability to meet the rising demand. Further, it did not have adequate capacity to meet the rising demand for the product.
- b. The capacity utilisation of the domestic industry is in excess of 100% for each year during the review period. There is a difference between the capacity figures reported in the annual report and in the response of the domestic industry.
- c. There are no losses incurred by the domestic industry as there is a profit as per publicly available information. There is no price underselling.
- d. There is no effect on its ability to raise capital investments as it has earned profits and also declared dividend in previous years.
- e. Due to inadequate domestic supply, domestic users of propylene glycol have no choice but to import the subject goods.

F.4 Examination by the Authority

- 23. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the submissions of the interested parties.
- 24. Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 25. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”

F.5 Likelihood of Continuation of Injury

26. The Authority has first examined whether there is likelihood of continuation of injury to the domestic industry on the basis its performance during the period of investigation (POI).
27. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any.

F.6 Volume effect**Assessment of Demand**

28. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods and the sales volume of the domestic industry have been added to the total imports into India, which has been summarized as under:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Imports from Subject Countries	MT	5384	9077	12956	11184
Imports from Other Countries	MT	2089	3199	1648	2018
Total imports	MT	7473	12276	14604	13201
Sale of domestic industry	MT	15331	16359	17502	15473
Demand	MT	22804	28635	32106	28674

29. The Authority notes that the demand has shown a positive trend and increased significantly in the period of investigation as compared to the base year. The growth in demand during period of investigation over the base year was about 25.75 %.

Import volumes and market share

30. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that "while examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India ...". Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.
31. The table below summarises the position with regard to import volumes and market share: -

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Imports from					
Subject Countries	MT	5384	9077	12956	11184

Other Countries	MT	2089	3199	1648	2018
Total Imports	MT	7,473	12,276	14,604	13,201
Indian Production	MT	15,950	16,426	16,875	16,069
Demand	MT	22,804	28,635	32,106	28,674
Subject imports in relation to					
Total Imports	%	72.05%	73.94%	88.72%	84.72%
Production	%	33.75%	55.26%	76.78%	69.60%
Consumption	%	23.61%	31.70%	40.35%	39.00%
Market share of domestic industry in demand	%	67.23%	57.13%	54.51%	53.96%

From the above, the Authority notes that:

- (i) The volume of imports of the subject goods from the subject countries in absolute terms has increased significantly in the period of investigation as compared to the base year.
- (ii) Imports from the subject countries have increased significantly in POI in relation to the total imports, production and consumption in India.
- (iii) The share of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation as compared to the base year.

Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

32. In order to ascertain the price effect of the imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry, the Authority has examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared the net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Price from Subject Countries	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting amount	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting range	Range	(0-5)%	0-5%	5-10%	(0-5)%

33. From the above, the Authority notes that while the imports from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry in the 2006-07 and 2007-08 periods, but a negative price undercutting is seen during the POI.

Price suppression/depression

34. In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry, the Authority has compared the cost of production and the net selling price of the domestic industry along with the landed price of imports over the injury period, which is given in the following table:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	103	115
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	93	108
Average Landed Price of imports from Subject Countries	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	88	114

35. The Authority notes that whereas both the cost of production and the net selling price increased over the injury period, the increase in the net selling price was much lower than the increase in the cost of production.

Economic Parameters relating to the Domestic Industry

36. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to determination of consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production, sales, capacity and capacity utilization

37. The production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
--	------	---------	---------	---------	---------

Installed Capacity	MT	13250	13250	13250	13250
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	15950	16426	16875	16069
Trend	Indexed	100	103	106	101
Capacity Utilization (%)	%	120%	124%	127%	121%
Trend	Indexed	100	103	106	101
Sales volumes	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	112	100
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	114	101

The above data shows that:

- The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased up to 2007-08 but declined thereafter in the 2008-09, the period of investigation.
- The domestic industry has been able to produce more than its capacity level from 2005-06 to 2008-09. In other words, capacity utilization is more than 100% throughout the injury period.

Profitability

38. The cost of sales, net sales realization & profit/loss of the domestic industry is shown below:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	103	116
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	93	108
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	45	71

Profit/Loss on domestic sales	Rs.Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	88	51	71
Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Profit before Interest	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	51	73
Net Fixed Assets	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	59	138
Working Capital	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	100	45
Capital Employed – NFA	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	81	87
Return on Capital Employed (NFA Basis)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	63	84
Depreciation	Rs./Lacs	***	***	***	***
Cash Profit	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	52	72

39. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has been declining till 2007-08 but has then improved during the POI. The return on capital employed and cash profits have followed the same trend as that of profits.
40. It is seen from the above table that on a year to year basis, the domestic industry was not able to increase the domestic selling prices in line with the increase in the cost of sales. The increase in cost of sales is much higher than the increase in net selling price of the domestic industry. However, inspite of this, the domestic industry is able to realize ***% return on capital employed during the period of investigation.

Market share

41. A comparison of the market share of the domestic producers and the imports from the subject countries in total demand of the subject goods in India shows that although the demand for the product has shown positive trend, yet the market share of domestic industry has declined significantly over the injury period, whereas the share of the subject countries has increased. But this needs to be seen in the context of over 100% capacity utilisation.

Market Share in Demand	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Subject Countries	%	23.61%	31.70%	40.35%	39%
Other Countries	%	9.16%	11.17%	5.13%	7.04%
Domestic industry	%	67.23%	57.13%	54.51%	53.96%

Employment and Wages

42. The position with regard to employment and wages is as follows:

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Employment No	***	***	***	***
Indexed	100	100	100	100
Wages Rs. Lacs	***	***	***	***
Indexed	100	126	128	140

Productivity

43. The Productivity of the domestic industry, as reflected in terms of production per employee as well as production per day, is given in the following table

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Production	MT	15950	16426	16875	16069
Employment	NO.	***	***	***	***
Productivity	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	106	101

44. It is observed that the productivity of the domestic industry improved till 2007-08 but has declined thereafter. The number of employees has remained constant throughout the injury investigation period and apparently there is no impact on the wages paid to them over the same period. However, the Authority notes that the domestic industry is a

multi-product company and hence the employment by the domestic industry and wages paid to them may not be a correct parameter to evaluate the injury in the instant matter.

Inventories

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Inventory in MT	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	63	48
Sales in MT	MT	***	***	***	***
Inventory for no. of days sales	Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	56	48

45. It is seen that the average inventory in terms of number of days' sales has declined over the injury period. In the base year, it was equivalent to *** days whereas in POI it decreased to *** days.

Ability to raise capital investment

46. There have been no capacity additions during the period of investigation. In view of sufficient profits earned by the domestic industry during the period of investigation, the ability to raise capital investments may not be adversely affected.

Magnitude of Margin of Dumping

47. The Authority notes that while there are positive dumping margins in respect of USA and Singapore but the same are negative in respect of Korea RP and European Union.

Growth

The Authority notes that Growth of the domestic industry in terms of parameters like production, sales, capacity utilization has been positive till 2007-08. However during the POI, a decline has been observed in these parameters. The profitability of the domestic industry has been declining up to 2007-08 but then improved during POI. The return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

49. The following factors have been brought before the Authority by the domestic industry for examination of likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. The domestic industry has, *inter alia*, submitted the following:

- (i) That the producers from the subject countries are dumping the material in the Indian market. Though there is an increase in raw material prices, the export price of the exporters has not shown proportionate increase indicating absorption of cost by the exporters.
- (ii) That in case the duties are discontinued the injury to the domestic industry would recur.
- (iii) That the landed price of imports from each of the subject countries is much lower than the price domestic industry ought to get.
- (iv) That volume of the imports from the subject countries has increased in spite of the antidumping duty in existence.
- (v) That the producers are holding significant surplus capacities and their domestic demand is significantly below the capacities created by them.

Examination by the Authority

50. The Authority has examined the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury in the following paragraphs.
51. The Authority notes that although the imports from subject countries have continued and increased yet its impact in volume terms is not visible as the domestic industry has been able to produce more than its capacity level from 2005-06 to 2008-09 (that is throughout the injury period). Imports have apparently not impacted the sales as well.
52. As regards the impact of the imports on the prices of the domestic industry, even that is not apparent as the domestic industry has been able to realise *** % return on capital employed (on NFA Basis).
53. While the domestic industry has contended that exporters/producers in the subject countries are likely to resort to dumping of the subject goods in the Indian market due to the excess capacities in the subject countries but this claim has not been substantiated by them.
54. It has not been demonstrated by domestic industry that the cessation of the anti-dumping duty would lead to likelihood of recurrence of injury to the domestic industry and continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.

F.4 Causal Link

55. With regard to Causal link, the domestic Industry has submitted that it is a settled position of law that Causal link analysis is not required to be done in Sunset reviews. In this connection, they have relied upon the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005):

"118. We therefore agree with Mexico that this fundamental principle is expressed in Article VI of the GATT 1994 and in various provisions of the Anti-Dumping Agreement. The United States does not question this principle per se. However, this does not mean that a causal link between dumping and injury is required to be

established anew in a "review" conducted under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement. This is because the "review" contemplated in Article 11.3 is a "distinct" process with a "different" purpose from the original investigation."

"119. The Appellate Body has underlined that "[t]he nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature of the determination to be made in an original investigation", and that "[t]he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes."

"X. Findings and Conclusions

219. For the reasons set forth in this Report, the Appellate Body:

(a) in relation to causation:

(b) finds that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely injury, as a matter of legal obligation, in a sunset review determination under Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and that, therefore, the USITC was not required to demonstrate such a link in making its likelihood-of-injury determination in the sunset review at issue in this dispute;"

56. The Domestic Industry has further submitted that there are good technical and logical reasons for not applying the requirement of Causal link in a Sunset review case. Extension of the anti-dumping duties is envisaged even if there are no imports during the review investigation period. Further, the test for extension of the period of duties under Section 9A (5) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
57. The Authority has examined the submissions of the Domestic Industry with regard to the significance of Causal link in a Sunset review investigation. It is important to note under Section 9A(5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. This has also been the consistent practice of the Designated Authority and is also borne out from the jurisprudence on the issue.
58. Without going into the merits of the arguments put forth by the Domestic Industry, the Designated Authority has examined the Causal link aspect which is discussed in the following paragraphs.

Volume and Prices from the Other Countries

59. It is noted that from the import statistics that the subject goods have been imported from one other country namely China PR in significant quantities at relatively cheaper prices. No explanation has been provided by the domestic industry as to why it does not consider that it is getting injured from these imports as against the imports from the subject countries.

Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

60. It is noted that there is no contraction of demand. On the other hand, the demand of the subject goods has increased by about ***% in the period of investigation as compared to the base year. There is also no indication of any change in the consumption pattern as is apparent from the sales pattern of the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers

61. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The Domestic Industry competes with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic Industry is determined by the landed price of the subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Development of Technology and Export Performance

62. No party has raised any issue with regard to technology as being the cause of injury to the domestic Industry. There has been small quantum of exports of the subject goods by the domestic industry. In any case, the Authority has considered profitability and other price parameters only in respect of domestic operations.

Productivity

63. There is no decline in the productivity and the same has increased over the injury investigation period.

64. Magnitude of Injury Margin

- The non-injurious price has been determined for the domestic industry as a whole.
- The non-injurious price determined has been compared with the weighted average landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin as shown below:

65. Injury Margin Calculations

The details relating to injury margin are as follows:

	Unit	2008-09
Non Injurious Price	Rs./MT	***
Landed Price from Subject Countries		
EU	Rs./MT	***
Korea	Rs./MT	***
Singapore	Rs./MT	***
USA	Rs./MT	***

Injury Margin		
EU	Rs./MT	(***)
Korea	Rs./MT	***
Singapore	Rs./MT	***
USA	Rs./MT	(***)
Injury Margin %		
EU	%	(***)
Korea	%	***
Singapore	%	***
USA	%	(***)
Injury Margin Range		
EU	% Range	(7-12)
Korea	% Range	2-6
Singapore	% Range	12-18
USA	% Range	(1-5)

the It is noted that the injury margin from Korea RP and Singapore is positive and injury margin from EU and USA is negative.

FINAL FINDINGS

66. The Authority, after considering the foregoing and as well as the comments on the disclosure statement, concludes that there is no current injury to the domestic industry from the imports from the subject countries and also notes that there is no case of likelihood of recurrence of injury due to dumping of the subject goods in the instant matter.
67. In view of the above, the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of Anti-dumping duty in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries as notified vide Notification No. 105/2004 dated 8th October 2004 and subsequently extended up to 7th July 2010 vide notification No.117/2009 dated 13th October 2009 in terms of Section 9 (A) (5) of the Act.
68. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority